

take care of the country. But I can assure my friend that if there is any possibility of having the distress sale, they can bring to my notice. Immediately we shall make certain arrangements.

SHRI VAYALAR RAVI: It is not a question of salt production. But what I say is that all trade in salt carried on by STC is only with the Bangladesh Government. May I know from the hon. Minister whether he reviews this policy because in Bangladesh the private trade is flourishing and because the export and import of that country is through the private trade only. Our trade is suffering because we are carrying on our trade in regard to certain items only through the STC. Do you propose to reconsider this proposal of carrying on the entire trade through STC or through private parties?

SHRI MOHAN DHARIA: So far as salt is concerned, it is both through STC and also through private traders. It so happened that until 2-9-1977 an export of about 2.36 lakhs tonnes had taken place entirely by private exporters and the outstanding contracts involved amounted to 3.73 lakhs of tonnes. Here, my hon. friend wants that the whole thing should be canalised. It all depends from item to item. The decisions are taken having regard to the interests of the country as such and if at all we feel that in the interest of the country a particular item should be canalised, we shall not hesitate in canalising that.

श्री राम कृष्ण बेरवा : प्रधम महोदय, बंगला देश के साथ जो नमक के मामले में समझौता हुआ था, उसकी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर सकी है क्योंकि उत्पादन कम हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सांघर झील है और उसमें काप्री झरना में नमक मिलता था लेकिन अब वहाँ पर स्फोरिजन तीन बार हुआ है अब वहाँ के कार्टेज भी नहीं हैं। जनता सरकार ने 10 लाख टन सॉल्ट को रोडकार-वेने की बत

घपने घोषणा पत्र में कहीं है और बार-बार इस हाउस में भी इस बात को कहा है। कुछ कंठिनाइयों की वजह से नमक का उत्पादन बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने उद्योग मंत्रालय से इस बारे में कोई सलाह माँगी है और अगर किया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उसमें क्या प्रगति हुई है।

श्री मोहन धारिया : उद्योग मंत्रालय से हमारा हर समय सम्बन्ध रहता है और एक्सेपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में भी उनसे बातचीत करने हैं। नमक का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी उद्योग मंत्रालय काफी प्रयत्न कर रहा है।

Basis on which Hotels are Star-Categorised

*217 **SHRI MANORANJAN BHAKTA:** Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the basis on which hotels are star-categorised at present;

(b) the number and names of hotels of different star-categories in the country; and

(c) whether Government propose to change the present criteria of classification of hotels into different star-categories and if so full details thereof and the action taken so far?

सर्वदल और-नाकर विधान मंत्री (श्री सुखदेवराज-जीविक) : (क) क्योंकि होटलों के वर्गीकरण के लिए जिन मानक्यों का अनु-संधान कर-वर्ष-यहूँ तक किया जा रहा था, अब वे पुराने पत्र-कुने हैं, इसलिए इस-अयम-जम्का-सुन्दर-किया-या-रहा है।

(ख) इस समय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर 280 होटल हैं जिनमें से 152 होटलों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा चुका है। वर्गीकृत होटलों (152) की श्रेणी तथा नामों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एक० टी०— 243/77]

(ग) होटलों का वर्गीकरण वर्तमान "स्टार प्रणाली" पर ही करते रहने का प्रस्ताव है। परन्तु, विभिन्न स्टार वर्गों के मानदण्डों में संशोधन करने की जरूरत है। मानदण्डों का पुनरीक्षण होटल उद्योग के परामर्श से किया जा रहा है।

SHRI MANORANJAN BHAKTA:
There is acute shortage of hotel accommodation for people from the low income group, throughout the country. We are always having 5-Star, and 3-Star and other Star-based hotels. What does the Government propose to do for the accommodation of low income groups at different places?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : कम आय वाले यात्रियों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सक्रिय विचार कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारी योजना है कि देश के चार मेट्रो-पालिटन सिटीज—दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता—में सस्ता आवास उपलब्ध करने की दृष्टि से जनता होटल बनाने का काम शुरू किया जाये। इस दिशा में कितनी प्रगति हो पायेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्लानिंग कमिशन से कितनी धनराशि उपलब्ध होती है। लेकिन दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1250 कमरों के एक जनता होटल का कार्य शुरू करने के बारे में सक्रिय विचार चल रहा है। उम्मीद है कि हम यह काम बहुत लघु ही शुरू करेंगे।

SHRI MANORANJAN BHAKTA:
The Minister has specifically stated that he is peaking about having the Janata hotels in big cities. My constituency is Andaman and Nicobar Islands; and there are other remote areas; where inland tourists used to go. In some cases, tourists even from other countries are coming. What is the proposal before the Government for accommodating people from low income groups in such outlying areas?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : केन्द्रीय सेक्टर में हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसे उसका जिक्र किया है। जहाँ तक विभिन्न राज्यों में सस्ते होटल बनाने का प्रश्न है, हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे इस तरह के सस्ते होटल बनाने के लिए पग उठावें। केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से उन्हें सहायता देने पर भी विचार किया जायेगा। यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि उन्हें वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर निजी सेक्टर के लोग भी सस्ते आवास के होटल बनाने के लिए भागे आते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सहायता तथा सुविधाएँ देने पर विचार किया जायेगा।

SHRI MANORANJAN BHAKTA:
The Minister has spoken about State governments; but what about the Union Territories? They are directly under the Central Government. What does the Central Government propose to do about them?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : सस्ता आवास बनाने का विचार इस सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है। (ब्यबजान) माननीय सदस्य शायद मुझे टोकना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पहले यह काम बहुत व्यापक पैमाने पर शुरू नहीं हुआ था। ट्रिस्ट लाज बनाने के बारे में कुछ काम हुआ है। कुछ यूब होस्टल भी बने थे और युवा पर्यटकों और सामान्य लोगों को डारमिटिटीज में

सस्ता आवास देने की कोशिश हुई है। लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य नहीं हुआ है। अब हम लोग व्यापक पैमाने पर सस्ता आवास उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक यूनिवर्सल टैरीटरीज का सम्बन्ध है, यह तो वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि हम वहां कितनी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि सम्पन्न लोगों के लिए जो व्यवस्था हुई है, चूक कम एप्लूएन्ट क्लास के लोग उनमें ज्यादा हैं, इसलिए उन के लिए सस्ते आवास की और अधिक व्यवस्था करने की हमारी कोशिश है।

श्री रामजी लाल सुमन : मंत्री महोदय ने चार महानगरों के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। आगरा देश के हिमाचल में ही नहीं विश्व के हिसाब में भी एक पर्यटन स्थल है और दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं और जो ताजमहल को देखने जाता है वह फनहपुर सीकरी भी देखने अवश्य जाता है। इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहां पर कोई आवास व्यवस्था नहीं है। क्या आप वहां पर सस्ते होटलों की व्यवस्था करेंगे? यदि सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह स्वयं कर सके तो क्या जनता को जो वहां होटल बनवाना चाहती है सरकार सस्ती जमीन उपलब्ध कराएगी और साथ ही साथ सरकारी वित्तीय सहायता से कम व्याज पर ऋण दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : निजी उद्योग में से जो लोग इस काम के लिए भागे आएंगे उसमें लिए जो मदद हम कर सकते हैं सरकारी सहायता से ऋण आदि दिलाने की अवश्य की जाएगी। इस समय किसी स्थान में होटल बनाने के बारे में भी कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर जो भी आर्थिक साधन उपलब्ध होंगे निश्चित रूप से हमारी

कोशिश होगी कि सस्ती आवास व्यवस्था हम करें।

श्री रामचारी शास्त्री : देवरिया जिले में कुशीनगर जो लाई बुद्ध का निर्वाण स्थल है वहां पर भारत के ही नहीं विश्व के बौद्ध भ्राते हैं। वहां पर जो होटल है उसका किराया 35 रुपये प्रतिदिन है जो कि प्रशांका होटल के बराबर है। उस धर्मस्थल के महत्व को देखते हुए और इसको देखते हुए कि देश में ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों के लोग भी वहां बहुत भ्राते हैं और 35 रुपये प्रतिदिन के आवास के नहीं दे सकते हैं, सरकार सस्ते आवास की वहां पर जल्दी व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : मैंने निवेदन किया है कि जहां तक बौद्ध पर्यटन केंद्रों का सम्बन्ध है सरकार निश्चिन्त रूप में उन 4 बाजे में विशेष ध्यान देगी। उनमें लिए मास्टर प्लान बना रहे है। कोशिश यह है कि जितनी जल्दी हो सके हम वहां सस्ते आवास की व्यवस्था कर दें।

SHRI K. RAMAMURTHY: This question relates to star hotels. The Janata Government have announced a policy decision that they are going to implement prohibition throughout the country in four or five years. But, at the same time, I find that in-awarding stars to a hotel, the attachment of bar is given extra marks. Will the Government come forward with a policy to scrap this condition of awarding extra marks to those hotels attached with bars?

श्री पुष्पोत्तम कौशिक : यह तो सरकार की जो मंच विधेय नीति बन रही है उस पर निर्भर करता है जो भी नीति होगी उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा।

SHRI K. RAMAMURTHY: If the Government want to introduce prohibition, how is it that they themselves impose a condition of awarding stars on the basis of the bar attached to the hostels?

श्री पुणवोलसम कौशिक : किसी होटल में मयखाने में शामिल कर देने पर कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं दिया जाता है।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN. This question is not exactly about hotels. I notice that an increasing number of school and college students come to see the capital of India, particularly during the session period or on other important occasions. I have come across many instances, when they had to stay on the platform of the Railway station because they had no other place to go. Will the Minister be pleased to make some arrangements, I would not call them dharamsalas, but some arrangement of that style, not one star or two star hotels but dormitories where the students can stay for two or three days. Will he make some such arrangements in the capital city of Delhi?

श्री पुणवोलसम कौशिक : मुझे बहुत खुशी हुई है कि माननीय सदस्य का मुझसे इस विषय में हमको मिला। निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है। यहाँ पर यूथ होस्टल है, यूथ होस्टल रीसॉर्सेशन भी है और वहाँ पर बराबर युवा पर्यटकों के ठहरने का प्रबन्ध होता है। जो यूथ ग्रुप में भी आते हैं, तो मैंने बताया कि उनका भी टैरिफ 15 रुपये होगा। एक साथ भ्रमण बढ़के आते हैं, तो एक कमरे में उनको और सस्ती जगह मिले, इसको भी व्यवस्था की जा सकती है।

श्रीमिनिंग साइड्स भी यहाँ पर है, जिनका उपयोग टूरिस्ट्स के लिये किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि

सरकार बराबर जोर दे रही है कि यूथ मूवमेंट को ठीक ढंग से बढ़ाने के लिये आवास व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। मैं माननीय सदस्य को प्रशस्त करना चाहता हूँ कि यूथ मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, यूथ लोगों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सकेगी हम करेंगे।

SHRI RAGAVALU MOHANARAN-GAM: I come from one of the historical places. You have not allowed me to ask a question.

MR. SPEAKER: Every party has been given a chance. Your party has also been given.

SHRI RAGAVALU MOHANARAN-GAM: Even the size of the Member does not count!

MR. SPEAKER: That I know!

SHRI RAGAVALU MOHANARAN-GAM: My question will be very brief.

MR. SPEAKER: I have called the next question. No further discussion.

Memorandum from All India P & T and other Central Government Pensioners' Association

*248 **SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether he has received a memorandum from the All India Posts and Telegraphs and other Central Government Pensioners' Association regarding the restoration of pension from 3/8th level to 4/8th level after full recovery of Death-cum-Retirement Gratuity amount paid in lieu of 1/8th reduction; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?